बड़ा कदम : मोदी सरकार बदलेगी ग्राम पंचायतों के संचालन का मॉडल

एआइ से होगी बैठकों की निगरानी, सरपंचों की नहीं चलेगी मनमानी

जितेन्द्र चौरसिया
patrika.com

नई दिल्ली. देश की 2.68 लाख ग्राम पंचायतों को हाईटेक करने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पूरे देश की ग्राम पंचायतों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी (एआइ) की निगरानी में लिया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में हवा-हवाई तरीके से पंच-सरपंच काम नहीं कर सकेंगे और न बैठकों के मिनिट्स में मनमाने तरीके से फेरबदल कर पाएंगे।

नरेंद्र मोदी सरकार ग्राम पंचायतों की बैठकों की मॉनिटरिंग व डाटा एनालिसिस के लिए एआइ फीचर्स लागू कर रही है। इसके तहत ग्राम पंचायतों की बैठकों के पूरे मिनिट्स एआइ से रिकार्ड होकर फाइनल होंगे। इसके लिए ई-ऑफिस की तर्ज पर ही पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम रहेगा। केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने एनआइसी के सहयोग से इसे तैयार किया है। यह काम चरणबद्ध तरीके से अगले महीने से शुरू हो सकता है। ग्राम पंचायतों पर एआइ फीचर्स लागू करना आधुनिक डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक डिजिटलीकरण का अधिकतर काम शहरों तक सिमटा है। इसके पहले केवल ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने व सैटेलाइट टॉप-बॉक्स तक के काम हुए हैं। अब एआइ साफ्टवेयर का प्रयोग शुरू होगा।

फैक्ट फाइल

2.68 लाख ग्राम पंचायतें पूरे देश में

6.65 लाख गांव पूरे भारत में पंजीकृत

83.3 करोड़ लोग गांवों के निवासी

68.86% देश की आबादी ग्रामीण

प्रमुख राज्यों में कितनी पंचायतें

23,006 ग्राम पंचायत **मध्यप्रदेश** में

11,304 ग्राम पंचायत **राजस्थान** में

11,693 ग्राम पंचायतें **छत्तीसगढ़** में

गड़बड़ी व भ्रष्टाचार रोकने में मददगार

ग्राम सभा के बैठकों के मिनिट्स एआइ से रिकार्ड होकर बनेंगे तो स्थानीय स्तर की गड़बड़ी-भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि, इस आनलाइन सर्वर पर मौजूद डाटा के हिसाब से केंद्रीय मानीटरिंग के जरिए कभी भी डाटा व उपयोग सत्यापन हो सकेगा।